

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहफाम हुकम की में जा	हुकम
16/11/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20.2.23 को पेश हो।		हि खा पुल्वीगि बीधा पदान प्रावट बीद क प्रा ने र
20.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभावकगणों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली वास्ते कार्यवाही दिनांक 10.7.23 को पेश हो।		
10.7.23	पत्रावली पेश हुई वकील उपाधी उपर ही बहस प्रापत्र न.प्र. हेतु अवसर चाहा। पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं अन्तिमतम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25-7-23 को पेश हो।		
25-7-23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पूर्व आदेश की पालना में अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10.10.23 को पेश हो।		
10/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपर ही बहस प्रापत्र न.प्र. सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/10/23 को पेश हो।		
20/10/23	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है बहस न.प्र. में वकील उपाधी ने अपने प्रापत्र में वगिति तथ्यों को दोहराते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील उपाधी ने निवेदन		



Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

कि खसरा संख्या 3641 के बजाम
प्राथमिक को ख.सं. 5202 की 5
बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकार
प्रदान किये जाने चाहिए वे, क्योंकि
आवटन की तारीख से ही इस 5
बीघा भूमि पर काबिज काश्त
करने चले आ रहे हैं। यह कि प्रत्यार्थी
प्राथमिक को हर वर्ष द्वारा 31 का
नोटिस देते हैं एवं पेलन्टी लगाते हैं,
एवं बेदखल करने की धमकियां
देते हैं अतः प्राथमिक को अधिकार
प्राप्त है कि अप्राथमिक के विरुद्ध
अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये।
हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र
उस्तुत रिजार्ड दस्तावेज आदि का
अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया इस
में प्रार्थी सिवायचरु भूमि पर काबिज
होना स्वीकार करता है, इसलिए
सिवायचरु भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा
जारी किया जाना न्यायालय उचित
नहीं समझता है। विवादित प्राराजी
सिवायचरु होने के कारण सुविधा
सन्तुलन एवं अपूर्णनीय अति ऊ
बिन्दु भी प्राथमिक के पक्ष में सिद्ध
नहीं होता है। अतः न्यायालय उक्त
विवेचन के आधार पर प्राथमिक का
प्रार्थना पर अस्वीकार किया जाना
उचित समझता है। अतः प्राथमिक का
प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज किया जाता है। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
नैनी (बुन्दी)